



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 24]

नई दिल्ली, सोमवार, जनवरी 10, 2000/पौष 20, 1921

No. 24]

NEW DELHI, MONDAY, JANUARY 10, 2000/PAUSA 20, 1921

विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्रालय

(विधि कार्य विभाग)

(न्यायिक अनुभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 6 जनवरी, 2000

सा.का.नि. 25 (अ) .— राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत के राजपत्र, (असाधारण) भाग-II, खंड-3, उपखंड (i) तारीख 2 जून, 1999 में प्रकाशित भारत सरकार के विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्रालय की अधिसूचना सं. सा.का.नि. 403 (अ), तारीख 2 जून, 1999 में निम्नलिखित संशोधन करते हैं :—

उक्त अधिसूचना में पाद टिप्पण के पश्चात् निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :—

स्पष्टीकारक ज्ञापन

चूंकि बारह वर्ष के पश्चात् फीस का पुनरीक्षण किया जा रहा है अतः सरकार से इसे 1 अप्रैल, 1998 से भूतलक्षी प्रभाव देने का विनिश्चय किया है। यह भी प्रमाणित किया जाता है कि इस संशोधन से किसी व्यक्ति के हित पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा।

[सं. एफ. 18/(1)/98-न्याय]

कृष्णा कुमार, संयुक्त सचिव और विधिक सलाहकार

MINISTRY OF LAW, JUSTICE AND
COMPANY AFFAIRS

(Department of Legal Affairs)

(Judicial Section)

NOTIFICATION

New Delhi, the 6th January, 2000

G.S.R. 25 (E).—In exercise of the the powers conferred by the proviso to article 309 read with article 76 of the Constitution, the President hereby makes the following amendments to the notification of the Government of India in the Ministry of Law, Justice & Company Affairs (Department of Legal Affairs) bearing GSR 403(E) dated 2nd June, 1999 published in the Gazette of India (Extraordinary) Part II, Section 3, Sub-Section (i) dated 2nd June, 1999, namely :—

In the said notification, after “Foot-Note”, the following shall be substituted, namely :—

EXPLANATORY MEMORANDUM

Since the revision of fee is being done after twelve years, it has been decided by the Government to give retrospective effect with effect from 1st April, 1998. It is also certified that the present amendment will not affect adversely the interest of any person.

[No. F. 18(1)/98-Judl.]

KRISHNA KUMAR, Jt. Secy. & Legal Adviser

